

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-113

जिसका उत्तर 06 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों में जल का अभाव

*113. श्री एन. गोकुलकृष्णन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि वर्ष 2016 के दौरान भारत को जल के अभाव के परिणामस्वरूप लगभग चौदह टेरावॉट घंटे के ताप विद्युत उत्पादन की क्षति हुई है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2015 से देश के संपूर्ण विद्युत उत्पादन में बीस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को रद्द करना पड़ा है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि देश के लगभग चालीस प्रतिशत ताप विद्युत संयंत्रों को जल उपलब्धता के संबंध में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"ताप विद्युत संयंत्रों में जल का अभाव" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 06.03.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 113 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : कभी-कभी ताप विद्युत यूनिटों को जल उपलब्धता में अवरोध के कारण आउटेज का सामना करना पड़ता है। ताप विद्युत केंद्रों द्वारा वर्ष 2016-17 में जल की कमी के कारण 9.57 टेरावाट घंटे की आउटेज हानियां हुईं जो विद्युत के कुल उत्पादन का लगभग 0.82% थीं।

(ख) : तथापि, जल की कमी के कारण आउटेज की वजह से उत्पादन की हानि से विद्युत उत्पादन के विकास में समग्र कमी नहीं आती है क्योंकि जल की कमी के कारण यदि कोई हानि होती है तो यह देश में अन्य यूनिटों से उत्पादन के माध्यम से पूरी की जाती है।

(ग) और (घ) : जी, नहीं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1275

जिसका उत्तर 06 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत की कीमतों में वृद्धि

1275. श्री संजय सेठ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत तीन वर्षों में हाजिर (स्पॉट) बाजार विद्युत कीमतों और भारतीय विद्युत विनिमय की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या पवन और जलविद्युत संयंत्रों के उत्पादन में कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के और अधिक स्रोतों के उपयोग में गिरावट आई है;
- (घ) उत्पादन में उक्त गिरावट के क्या कारण हैं; और
- (ङ) इन बढ़ी हुई कीमतों से उपभोक्ता किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं और सरकार द्वारा इस मसले के समाधान के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) नामक 2 पावर एक्सचेंज, जहाँ विद्युत का व्यापार किया जा रहा है, हैं। इन पावर एक्सचेंजों में प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लॉक में डे अहेड मार्केट (डीएएम) पर विद्युत की कीमतों का पता लगाया जाता है। प्रत्येक समय ब्लॉक में ये कीमतें बदलती रहती हैं जिससे किसी निर्धारित समय पर मार्केट में विद्युत मांग और आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करते हुए किसी दिन कीमतें बदल जाती हैं।

विगत 3 वर्षों के दौरान इन पावर एक्सचेंजों की डीएएम पर भारित औसत कीमतें निम्नानुसार हैं:

वर्ष	आईईएक्स पर कीमत (₹./केडब्ल्यूएच)	पीएक्सआईएल पर कीमत (₹./केडब्ल्यूएच)
2014-15	3.49	3.09
2015-16	2.72	2.66
2016-17	2.48	2.56

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पावर एक्सचेंजों के माध्यम से व्यापार की गई विद्युत की औसत बाजार निकासी कीमतें विगत 3 वर्षों के दौरान काफी घट गई हैं।

तथापि, सितंबर, 17 - नवंबर, 17 माह के दौरान कुछ दिनों के दौरान 15 मिनट के कुछ समय ब्लॉक में 9 रु. से 11 रु. प्रति किलोवाट घंटा के स्तर तक स्पॉट मार्केट विद्युत कीमतें बढ़ने के कुछ दृष्टांत थे। इन महीनों के दौरान इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में मासिक औसत बाजार निकारी कीमतें (एमसीपी) 4.09 रु./किलोवाट घंटा (सितंबर, 17), 4.08 रु./किलोवाट घंटा (अक्टूबर, 17) और 3.55 रु./किलोवाट घंटा (नवंबर, 17) थीं।

(ग) और (घ) : वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान पवन एवं जल विद्युत संयंत्रों से उत्पादन नीचे दिया गया है:

	2014-15	2015-16	2016-17
पवन (एमयू में)	33768.30	33029.39	46004.34
हाइड्रो (एमयू में)	129244	121377	122378
कुल नवीकरणीय	61785	65781	81548

उपरोक्त आंकड़ों से यह अवलोकन किया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पवन और जल विद्युत उत्पादन घटा था लेकिन वित्तीय वर्ष 2016-17 में बढ़ा था। वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से समग्र उत्पादन निरंतर बढ़ा है।

(ङ) : पावर एक्सचेंजों के माध्यम से व्यापार की गई विद्युत का हिस्सा देश में खपत की जा रही कुल विद्युत का केवल लगभग 3% है। अतः पावर एक्सचेंज में विद्युत कीमतों में किसी दिन में कुल 96 समय ब्लॉकों में से प्रत्येक 15 मिनट के 2 से 3 समय ब्लॉकों के दौरान किसी अल्पावधि फ्लैकचुएशन का प्रभाव उपभोक्ताओं के लिए निरर्थक प्रभाव होगा। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग उपयुक्त विनियमों के माध्यम से भारत में पावर एक्सचेंजों का उचित, निष्पक्ष, दक्ष और सुदृढ़ कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1276

जिसका उत्तर 06 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

उत्तराखण्ड में पंचेश्वर बांध से विद्युत उत्पादन

1276. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंचेश्वर बांध से कुल कितनी मेगावाट बिजली पैदा होगी;

(ख) क्या राज्य के संसाधनों का दोहन राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने पर राज्य को रॉयल्टी दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो उत्तराखण्ड के पंचेश्वर में बनने वाले बांध से जितने मेगावाट बिजली तथा जितनी रॉयल्टी राज्य हेतु निर्धारित की गई है, उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : पंचेश्वर बहु-उद्देश्यीय परियोजना से संभावित कुल विद्युत उत्पादन 5040 मेगावाट है।

(ख) से (घ) : भारत सरकार की मौजूदा जल विद्युत नीति के अनुसार, गृह राज्य (अर्थात् राज्य, जहां परियोजना स्थित है) परियोजना से कुल विद्युत उत्पादन से 13 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत (मेजबान सरकार के लिए 12 प्रतिशत तथा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए अंशदान हेतु 1 प्रतिशत) के लिए पात्र है। किसी भी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में मेगावाट में विद्युत के ब्यौरे स्पष्ट किये जाते हैं। तथापि, पंचेश्वर के द्वि-राष्ट्रीय परियोजना होने के कारण इसकी डीपीआर को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1277

जिसका उत्तर 06 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को सहायता

1277. डॉ. वी. मैत्रेयन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएनजीईडीसीओ) और तमिलनाडु विद्युत बोर्ड की समस्याओं को दूर करने के लिए तमिलनाडु सरकार को पर्याप्त निधि प्रदान की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत दो वर्षों में कुल अनुदान में से कितनी राशि जारी की गई है;
- (ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु के लिए विद्युत आवंटन में वृद्धि करने का कोई निर्णय लिया है अथवा वृद्धि करने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने तथा चेन्नूर और उडनकुडी में स्थित विद्युत परियोजनाओं हेतु तमिलनाडु को सहायता देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड (टैनजेडको) का वित्तीय प्रबंधन इसके निदेशक मंडल और राज्य सरकार का उत्तर दायित्व है। एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय ने 2015-16 से टैनजेडको को 664.39 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) : तमिलनाडु में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विभिन्न केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से आबंटन 31.05.2014 को 4097 मेगावाट से 51.4 प्रतिशत बढ़ाकर 31.01.2018 को 6201 मेगावाट कर दिया है। भारत सरकार ने चेन्नूर में 4000 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) भी अभिचिन्हित की है। टैनजेडको ने उडनकुडी में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना (टीपीपी) के वित्तपोषण के लिए रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) से अनुरोध किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1278

जिसका उत्तर 06 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाओं का कार्यान्वयन

1278. श्री टी. जी. वेंकटेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूरे देश में एल ई डी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाओं को लागू करने जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समस्याएं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान पेश आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : 1.34 करोड़ परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को मार्च, 2019 तक ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटों से बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 05 जनवरी, 2015 को स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) की शुरुआत की थी। एसएलएनपी विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, अब तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 49 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं।

(ख) : ईईएसएल ने हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में मामला अध्ययन किये हैं। इन अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों का सार अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) : एसएलएनपी के कार्यान्वयन में अब तक किसी विशिष्ट समस्या का सामना नहीं किया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 06.03.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1278 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी मामलों के अध्ययन के परिणामों के निष्कर्षों का सार निम्नानुसार है:

1. **हिमाचल प्रदेश:** नमूना आधार पर ईईएसएल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के कार्यान्वयन के जरिए हासिल ऊर्जा और मौद्रिक बचतें निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	शहर	लगाई गई कुल लाइटें	परंपरागत लाइटों से मासिक ऊर्जा खपत (केडब्ल्यूएच में)	एलईडी से मासिक ऊर्जा खपत (केडब्ल्यूएच में)	मासिक ऊर्जा बचत (केडब्ल्यूएच में)	% बचत	प्रति माह मौद्रिक बचत (रुपए में)
1	शिमला	8516	358082	158199	199883	56%	9,89,419
2	धर्मशाला	2910	120345	52495	67850	56%	3,35,859
3	मंडी	2189	80003	34917	45086	56%	2,23,174
4	सुंदरनगर	1821	62822	27023	35799	57%	1,77,205
5	पाँवटा साहिब	1948	114525	50654	63871	56%	3,16,159
6	घुमारविन	608	22645	9911	12734	56%	63,033
7	मनाली	798	40912	18876	22036	54%	1,09,079
कुल		18790	799334	352075	447258	56%	22,13,928

(औसत प्रचालन घंटे प्रति दिन 11 माने गए हैं; 4.95/केडब्ल्यूएच भारतीय रुपए की यूनिट दर मानते हुए मौद्रिक बचत की गणना अनुमानित बचत दृष्टिकोण पर आधारित है)।

2. **राजस्थान:**

(i) **झालावाड़ स्ट्रीट लाइट परियोजना:**

नमूना आधार पर ईईएसएल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, झालावाड़ में स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के कार्यान्वयन के जरिए हासिल ऊर्जा बचतें नीचे दी गई हैं:

परंपरागत स्ट्रीट लाइटों की कुल मालसूची			
क्रम सं.	लैंपों का पूर्ववर्ती वाटेज (डब्ल्यू)	मात्रा	कुल किलोवाट
1	हाई प्रेशर सोडियम वपोर - 400	36	16
2	हाई प्रेशर सोडियम वपोर - 250	120	33

3	हाई प्रेशर सोडियम वपोर - 150	140	23
4	हाई प्रेशर सोडियम वपोर - 70	157	13
5	फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट - 40 वाट	1624	78
6	कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप - 20 वाट	372	7
कुल किलोवाट			170

एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाए जाने के बाद कुल मालसूची			
क्रम सं.	एलईडी लाइट का वाटेज	मात्रा	कुल किलोवाट
1	190	36	7
2	120	120	14
3	72	140	10
4	40	157	6
5	18	1624	29
6	12	372	4
कुल किलोवाट (नया)			71

ऊर्जा बचत संभाव्यता के अनुमान	
पूर्ववर्ती लोड (किलोवाट में)	170
नया लोड (किलोवाट में)	71
लगाए जाने के बाद लोड में कमी (किलोवाट में)	99
केडब्ल्यूएच में वार्षिक ऊर्जा बचत	395863
एमयू में वार्षिक ऊर्जा बचत	0.396
लोड में % कमी	58%

(औसत प्रचालन घंटे प्रति दिन 11 माने गए हैं और प्रचालन दिवस 365 माने गए हैं)।

झालावाड़ में एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना के कार्यान्वयन से स्ट्रीट लाइट लोड 170 किलोवाट से घटकर 71 किलोवाट हो गया है।

(ii) माउंट आबु स्ट्रीट लाइट परियोजना:

नमूना आधार पर ईईएसएल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, माउंट आबु में स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के कार्यान्वयन के जरिए हासिल ऊर्जा और मौद्रिक बचतें निम्नानुसार हैं:

परंपरागत स्ट्रीट लाइटों की कुल मालसूची			
क्रम सं.	लैंपों का पूर्ववर्ती वाटेज (डब्ल्यू)	मात्रा	कुल किलोवाट
1	हाई प्रेशर सोडियम वपोर - 400	106	42.4
2	हाई प्रेशर सोडियम वपोर - 250	43	10.8
3	हाई प्रेशर सोडियम वपोर - 150	492	73.8
4	हाई प्रेशर सोडियम वपोर - 70	144	10.1

5	फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट - 40 वाट	508	20.3
6	कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप - 36 वाट	202	7.3
7	कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप - 72 वाट	6	0.432
8	कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप - 15 वाट	3	0.045
9	कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप - 11 वाट	26	0.286
कुल किलोवाट			165.4

एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाए जाने के बाद कुल मालसूची			
क्रम सं.	एलईडी लाइट का वाटेज	मात्रा	कुल किलोवाट
1	120	76	9.12
2	70	669	46.83
3	15	737	11.055
कुल किलोवाट (नया)			67

ऊर्जा बचत संभाव्यता के अनुमान	
पूर्ववर्ती लोड (किलोवाट में)	165.4
नया लोड (किलोवाट में)	67
लगाए जाने के बाद लोड में कमी (किलोवाट में)	98.4
केडब्ल्यूएच में वार्षिक ऊर्जा बचत	394996
एमयू में वार्षिक ऊर्जा बचत	395
लोड में % कमी	59%

(औसत प्रचालन घंटे प्रति दिन 11 माने गए हैं और प्रचालन दिवस 365 माने गए हैं)।

माउंट आबु में एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना के कार्यान्वयन से स्ट्रीट लाइट लोड 165.4 किलोवाट से घटकर 67 किलोवाट हो गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1279

जिसका उत्तर 06 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

तेलंगाना में किसानों को मुफ्त विद्युत

1279. श्री राजकुमार धूतः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि तेलंगाना सरकार राज्य में किसानों को विद्युत की निःशुल्क आपूर्ति कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार तेलंगाना की तर्ज पर अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने किसानों को विद्युत निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करने का विचार रखती है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जारी किए गए प्रशुल्क आदेश के अनुसार, राज्य सरकार कारपोरेट किसानों के अलावा अन्य कृषि क्षेत्र (मांग पक्ष प्रबंधन उपाय अनिवार्य होने के साथ) को निःशुल्क लागत पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। विद्युत के उत्पादन पारेषण और वितरण में लागत लगती है तथा निरंतर आपूर्ति किए जाने के लिए लागत की वसूली की जानी होती है। यदि कोई राज्य सरकार उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी निःशुल्क विद्युत आपूर्ति करना चाहती है तो आपूर्ति की गई विद्युत की लागतें राज्य सरकार को वहन करने की आवश्यकता होगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1280
जिसका उत्तर 06 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ग्रामों का विद्युतीकरण

1280. कुमारी शैलजा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में तथा कई राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में विद्युत की लगातार कमी बनी रहती है;
- (ख) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में सरकार की क्या योजनाएं हैं;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ग्रामों में विद्युतीकरण के लिए कौन-सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और इसके लिए आवंटित निधि कितनी है; और
- (घ) इन योजनाओं के तहत लाभान्वित गांवों की संख्या कितनी है और शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक किया जाएगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों सहित सभी घरों को विद्युत उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का है। तथापि, भारत सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों सहित घरों की सभी श्रेणियों के लाभ के लिए संपूर्ण देश में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य के जरिए गांवों और घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। सभी गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों को 01 मई, 2018 तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के घरों सहित सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को 31 मार्च, 2019 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है। सभी घरों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों ने स्वयं को प्रतिबद्ध करते हुए भारत सरकार के साथ सभी के लिए 24x7 विद्युत दस्तावेज हस्ताक्षरित किए हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य योजनाओं के लिए आबंटित निधियां नीचे दी गई हैं:

(रुपए करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17
डीडीयूजीजेवाई (अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) घटक सहित)	3386.38	4500.00	8000.00*
एससीएसपी घटक के अंतर्गत प्रावधान	460.44	510.48	867.64
सौभाग्य	योजना 11.10.2017 को शुरू की गई		

* 5000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजटीय स्रोतों सहित।

राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 31.01.2018 तक संचयी रूप से 1,25,149 गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य तथा 4,87,892 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है।
